

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੰ. 1680] No. 1680] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2010/श्रावण 22, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2010/SHRAVANA 22, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

का.आ. 1995(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए प्रारुप नियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3316(अ), तारीख 21 दिसम्बर, 2009 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 31 दिसम्बर, 2009 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, 45 दिन की अविध समाप्त होने के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 दिसम्बर, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण (वधशाला) संशोधन नियम, 2010 है।
 - (2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के नियम 9 के में उप-नियम (1), में "उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या पशु कल्याण संगठन" शब्दों के स्थान पर "राज्य पशु कल्याण बोर्ड या कोई व्यक्ति जो अर्हित पशु चिकित्सक है और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा प्राधिकृत है, कम से कम प्रत्येक छह मास की अवधि में एक बार" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 27-1/2009-ए डब्ल्यू डी] हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचना संख्यांक का.आ. 270(अ) तारीख 26 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

3188 GI/2010

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2010

S.O. 1995(E).—Whereas the draft rules amending the Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001 were published, as required by sub-section (1) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) under the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 3316(E), dated 21st December, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 31st December, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 31st day of December, 2009;

And, whereas no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001, namely:—

- 1. (1) These rules may be called Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Amendment Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001, in rule 9, in sub-rule (1), for the words "any person or Animal Welfare Organisation authorized by its, may", the words "a State Animal Welfare Board or any person who is a qualified veterinarian and is authorised by the Animal Welfare Board of India, may, at least once in every six months period", shall be substituted.

[F.No. 27-1/2009-AWD]

HEM PANDE, Jt. Secy.

Note:—The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Notification Number S.O. 270(E), dated 26th March, 2001.